प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी, सचिव, उत्तरों चल शासन

सेवा में.

निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनॉक

/ 4 अगस्त, 2006

विषयः राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याःनियोजन-4/17596/रा0गा0न0वि/2006-07 दिनोंक 10-7-2006 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 270/XXIV-3/2006-2(81)05 दिनोंक 26-5-2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू० 1160.49 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू० 864.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू० 296.49 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू० 75.00 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को प्रश्नगतं योजना में शासनादेश संख्याः 233/ XXIV-3/2006 दिनोंक 27-04-2006 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू० 1200.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन है:--

(1)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विमाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक— 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा -202-माध्यमिक शिक्षा- आयोजनागत - 00 -16- राजीव गोंधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण-24- वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभागके अशासकीय संख्या- 612 दिनाँक 01.8.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(एस० के० माहेश्वरी) सचिव

सँख्याः 443 (1) / XXIV-3/2006 तद्दिनॉक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।

2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।

6-- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।

7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।

8- जिलाधिकारी, हरिद्वार।

9- कोषाधिकारी, हरिद्वार।

10-सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।

11- वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ट।

12- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)

,13 एन0आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

14- गार्ड फाइल।

उप सचिव

(2)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) - कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,

स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) – कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करना

स्निश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँ ति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय

कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

> (10) – निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष / संस्था

को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगें।

a